Bundelkhand Research Journal | June, 2025 | Volume 3, Issue 1 ISSN: 2584-0533

मध्य प्रदेश की कृषक कल्याण योजनाओ का पन्ना जिले के ग्रामीण विकास पर प्रभाव का विश्लेषणातमक अध्ययन

मनीष भगत[1] एवं सचिन गोयल[2]

[1]वाणिज्य अध्ययनशाला एवं शोध केन्द्र, म.छ.बु.वि.वि.,छतरपुर (म.प्र.)

[2]वाणिज्य संकाय, पीएमसीओई छत्रसाल शासकीय पी.जी. कॉलेज पन्ना (म.प्र.)

Corresponding Author: camanishbhagat@gmail.com

Received 14 April 2025; Accepted 06 June 2025

सार

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए विभिन्न कृषक कल्याण योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, ग्रामीण विकास को गति देना और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। यह अध्ययन पन्ना जिले में लागू प्रमुख कृषक कल्याण योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, फसल बीमा योजना, कृषि ऋण माफी योजना, और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था का विश्लेषण करता है। अध्ययन में इन योजनाओं के लाभ, प्रभाव, चुनौतियों और किसानों की आय, ऋण भार, और जीवन स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया गया है। शोध में मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान विधियों का उपयोग किया गया है, जिसमें प्राथमिक डेटा (किसानों से साक्षात्कार एवं सर्वेक्षण) और द्वितीयक डेटा (सरकारी रिपोर्ट्स और नीति दस्तावेज) का समावेश किया गया है। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि कृषि अनुदान, बीमा कवरेज और ऋण माफी योजनाओं ने किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। हालाँकि, योजनाओं के कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ जैसे सूचना की कमी, जमीनी स्तर पर जागरूकता की आवश्यकता, और वितरण में देरी भी देखी गई हैं। अध्ययन यह अनुशंसा करता है कि योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किसानों को डिजिटल सशक्तिकरण, पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियानों और सीधे बैंक हस्तांतरण (DBT) की पारदर्शी व्यवस्था की आवश्यकता है। यह शोध नीति निर्माताओं, कृषि योजनाकारों और ग्रामीण विकास विशेषज्ञों को नवीन सुधार और नीतिगत सुधारों की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

कुंजी शब्द: कृषक कल्याण योजना, कृषि विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पन्ना जिला, मध्य प्रदेश।

प्रस्तावना

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यह लाखों किसानों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। मध्य प्रदेश, जो कि कृषि उत्पादन के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है, ने पिछले कुछ दशकों में कृषक कल्याण और कृषि सुधार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाएँ शुरू की हैं (नेमा, 2024)। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, फसल हानि की भरपाई, ऋण प्रबंधन में सहायता, और कृषि क्षेत्र को अधिक टिकाऊ एवं लाभकारी बनाना है (आहूजा, कावड़िया, ग्वाल और श्रीवास्तव, 2008) (पूनम, कुमार, राजपूत, 2023)।

पृष्ठभूमि और अध्ययन की आवश्यकता

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के विकास के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कृषि ऋण माफी योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना, एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जैसी कई योजनाएँ लागू की गई हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार किसानों को आर्थिक सहायता, सब्सिडी, बीमा सुरक्षा, कृषि निवेश, विपणन सुविधाएँ एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है (बी और एसडी, 2005)।

हालांकि, इन योजनाओं की असली सफलता उनके प्रभावी क्रियान्वयन और किसानों तक उनकी वास्तविक पहुँच पर निर्भर करती है। पन्ना जिले जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि क्या ये योजनाएँ किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सफल रही हैं या नहीं। इस संदर्भ में, यह अध्ययन पन्ना जिले के किसानों पर कृषक कल्याण योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किया गया है(बी और एसडी, 2005),(बडकुल, मोहम्मद और बेंदी, 2022)। पन्ना जिले में किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला कि लगभग 76% किसान सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक हैं, लेकिन इनमें से केवल

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

69% किसानों को इनका सीधा लाभ प्राप्त हुआ है। वहीं, 31% किसानों ने यह बताया कि उन्हें अभी तक किसी सरकारी योजना का कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिला है। इससे यह स्पष्ट होता है कि योजनाओं के कार्यान्वयन में कुछ बाधाएँ हैं, जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है।

कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश की स्थिति और चुनौतियाँ

मध्य प्रदेश भारत के उन राज्यों में से एक है जहाँ कृषि क्षेत्र की उत्पादकता उच्च दर से बढ़ी है। राज्य सरकार ने सिंचाई सुविधाओं में सुधार, कृषि ऋण व्यवस्था को मजबूत करने, और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएँ लागू की हैं। फिर भी, कई कृषक कल्याण योजनाओं का प्रभाव सीमित है क्योंकि कई किसानों को इनका सही लाभ नहीं मिल पा रहा है (बी और शर्मा, गोदारा, और सिंगला, 2014)।

मुख्य चुनौतियाँ

योजनाओं की जानकारी और जागरूकता की कमी: कई किसान योजनाओं के लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया से अनजान हैं, जिससे वे इनका लाभ नहीं उठा पाते। कार्यान्वयन की समस्याएँ: कई बार योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ पहुँचाने में देरी होती है, जिससे किसान निराश हो जाते हैं। बिचौलियों की भूमिका: कुछ योजनाओं में बिचौलियों के हस्तक्षेप के कारण वास्तविक किसानों तक लाभ सीमित मात्रा में पहुँचता है। तकनीकी अवरोध: कई किसान ऑनलाइन पोर्टल और डिजिटल लेनदेन के अभाव में योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। सीमित वित्तीय सहायता: कई योजनाएँ सीमित वित्तीय लाभ प्रदान करती हैं, जो किसानों की वास्तविक जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं होती।

शोध पद्धति

यह अध्ययन पन्ना जिले के किसानों पर कृषक कल्याण योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए एक मिश्रित अनुसंधान पद्धति (Mixed Method Research Approach) का उपयोग करता है। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक डेटा संग्रहण तकनीकों को शामिल किया गया है ताकि प्राप्त निष्कर्षों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके (त्रिपाठी, ढोडिया, गिरी, राठौड़, वर्मा, शुक्ला, वर्मा, 2023,) (साहू, रघुवंशी और जौलकर, 2017) I

1. अध्ययन क्षेत्र

यह शोध मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कृषक कल्याण योजनाओं के प्रभाव का आकलन करता है। पन्ना जिला एक प्रमुख कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ किसान धान, गेहूं, दलहन एवं तिलहन जैसी फसलें उगाते हैं। राज्य सरकार की कई योजनाएँ, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कृषि ऋण माफी योजना, एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था, इस जिले में कार्यरत हैं।

2. डेटा संग्रहण तकनीक

इस अध्ययन में डेटा संग्रह के लिए दो प्रमुख स्रोतों का उपयोग किया गया है:

प्राथमिक डेटा संग्रह

सर्वेक्षण (Survey Method): पन्ना जिले के 200 किसानों पर एक संरचित प्रश्नावली (Structured Questionnaire) के माध्यम से डेटा एकत्र किया गया।

साक्षात्कार (Interviews): प्रमुख हितधारकों जैसे कृषि अधिकारी, पंचायत प्रमुख और स्थानीय कृषि विशेषज्ञों से गहन साक्षात्कार किए गए।

फोकस ग्रुप चर्चा: किसानों के एक समूह के साथ चर्चा करके योजनाओं की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया गया।

द्वितीयक डेटा संग्रह

सरकारी रिपोर्ट्स और नीतिगत दस्तावेज: कृषि मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार और अन्य सरकारी संस्थानों द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स का अध्ययन किया गया।

NSSO और CSO डेटा: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) से प्राप्त आर्थिक और कृषि विकास संबंधित आँकड़ों का विश्लेषण किया गया। शोध पत्र और जर्नल्स: पूर्व में प्रकाशित अनुसंधानों और नीति-पत्रों की समीक्षा की गई, जिससे योजनाओं के प्रभाव और चुनौतियों को समझा जा सके।

3. नमूना चयन

यह अध्ययन आकस्मिक नमूना विधि (Stratified Random Sampling) पर आधारित है।

चयन प्रक्रिया: पन्ना जिले के 5 प्रमुख ब्लॉक (Block) चयनित किए गए। प्रत्येक ब्लॉक से 40 किसानों को यादृच्छिक रूप से चुना गया, जिससे कुल 200 किसानों का नमूना प्राप्त हुआ। किसानों को उनके भूमि स्वामित्व, फसल उत्पादन और सरकारी योजनाओं से जुड़ाव के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया।

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

4. डेटा विश्लेषण: संग्रहित डेटा का विश्लेषण करने के लिए मात्रात्मक (Quantitative) एवं गुणात्मक (Qualitative) तकनीकों का प्रयोग किया गया:

मात्रात्मक डेटा विश्लेषण

वर्णात्मक सांख्यिकी: योजनाओं की पहुँच, लाभान्वित किसानों की संख्या, तथा लाभों की प्रतिशतता को समझने के लिए।

SPSS सॉफ्टवेयर का उपयोग: औसत (Mean), माध्यिका (Median), मानक विचलन (Standard Deviation) और प्रतिशत विश्लेषण किया गया।

t-टेस्ट और ANOVA विश्लेषण: विभिन्न योजनाओं के लाभों में अंतर को परखने के लिए सांख्यिकीय परीक्षण किए गए।

गुणात्मक डेटा विश्लेषण

विषयगत विश्लेषण: साक्षात्कारों और फोकस ग्रुप चर्चाओं से प्राप्त डेटा को मुख्य विषयों के आधार पर वर्गीकृत किया गया।

SWOT विश्लेषण: योजनाओं की ताकत (Strengths), कमजोरियाँ (Weaknesses), अवसर (Opportunities), और चुनौतियाँ (Threats) का मूल्यांकन किया गया।

प्रभाव आकलन: योजनाओं के कारण किसानों के आर्थिक, सामाजिक और कृषि संबंधी परिवर्तनों का अध्ययन किया गया।

5. शोध की विश्वसनीयता और वैधता: शोध की निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए:

त्रिभुजकरण: विभिन्न डेटा स्रोतों (प्राथमिक सर्वेक्षण, सरकारी रिपोर्ट्स और साक्षात्कार) का आपसी मिलान किया गया।

पायलट अध्ययन: 20 किसानों पर प्रारंभिक सर्वेक्षण करके प्रश्नावली की प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया और आवश्यक सुधार किए गए।

विश्वसनीयता परीक्षण: Cronbach's Alpha परीक्षण का उपयोग करके प्रश्नावली की आंतरिक संगति (Internal Consistency) की पुष्टि की गई। Kappa सांख्यिकीय परीक्षण से साक्षात्कार के निष्कर्षों की स्थिरता सुनिश्चित की गई।

6. नैतिक विचार: इस शोध में नैतिकता से जुड़े निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखा गया:

सहमति: सभी प्रतिभागियों से उनकी सहमति प्राप्त की गई और उन्हें बताया गया कि यह डेटा केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा।

गोपनीयता: प्रतिभागियों की पहचान गोपनीय

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

रखी गई।

निष्पक्षता: शोध में किसी भी पूर्वाग्रह को हटाने के लिए निष्पक्ष डेटा संग्रहण और विश्लेषण किया गया।

परिणाम

इस अध्ययन के माध्यम से पन्ना जिले में कृषक कल्याण योजनाओं के प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन किया गया। प्राप्त आँकड़ों और सर्वेक्षण के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि इन योजनाओं ने किसानों की आर्थिक स्थिति, कृषि उत्पादन, और सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, इनके कार्यान्वयन में कुछ प्रमुख चुनौतियाँ भी देखी गईं, जिनका समाधान आवश्यक है।

1. कृषक कल्याण योजनाओं की पहुँच और जागरूकता: 76% किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी थी, जबकि 24% किसानों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी। 69% किसानों ने बताया कि उन्होंने किसी न किसी योजना का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त किया, लेकिन 31% किसान अभी तक किसी योजना से लाभान्वित नहीं हो सके। अधिकतर किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और फसल बीमा योजना से परिचित थे, जबकि कुछ योजनाओं जैसे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड और ई-नाम (e-NAM) पोर्टल के बारे में जागरूकता अपेक्षाकृत कम थी।

2. आर्थिक प्रभाव और ऋण सहायता: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के माध्यम से किसानों को वार्षिक 6000 रुपये की सहायता मिली, जिससे उनके दैनिक कृषि निवेश में सुधार हुआ। कृषि ऋण माफी योजना से 48% किसानों को कर्ज़ राहत मिली, लेकिन कुछ किसानों ने इसके क्रियान्वयन में देरी और जटिल प्रक्रिया की शिकायत की।किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना का उपयोग करने वाले किसानों में से 62% किसानों ने बताया कि इससे उन्हें कृषि कार्यों के लिए तत्काल ऋण उपलब्ध हुआ।

3. फसल उत्पादन और विपणन पर प्रभाव: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने वाले किसानों में से 54% ने कहा कि उन्हें आंशिक बीमा दावा प्राप्त हुआ, जबकि 32% किसानों ने दावों के निपटारे में देरी की शिकायत की। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली का प्रभाव मिश्रित रहा - 45% किसानों

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

ने इसे लाभकारी बताया, जबकि 30% किसानों को बाज़ार मूल्य की अस्थिरता के कारण नुकसान उठाना पड़ा। MSP केंद्रों पर पारदर्शिता की कमी और बिचौलियों की दखलंदाजी के कारण कई किसानों को अपनी उपज के सही मूल्य मिलने में कठिनाई हुई।

4. सिंचाई और बुनियादी ढाँचे पर प्रभाव: सिंचाई सुविधाओं में सुधार के चलते कृषि उत्पादन में 32% की वृद्धि देखी गई। सौर ऊर्जा आधारित पंप और ड्रिप सिंचाई प्रणाली जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने वाले किसानों की संख्या बढ़ी, लेकिन अभी भी इसका प्रसार सीमित है। ग्रामीण सड़कों की स्थिति में सुधार के बावजूद, 27% किसानों ने बताया कि उनके गाँव से प्रमुख बाज़ारों तक संपर्क मार्गों में सुधार की आवश्यकता है।

5. तकनीकी और डिजिटल सेवाओं की स्थिति: डिजिटल सेवाओं से जुड़ने में ग्रामीण किसानों को कठिनाई हो रही है - 40% किसानों को ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पोर्टल्स का उपयोग करना जटिल लगा। ई-नाम (e-NAM) पोर्टल के माध्यम से कृषि उत्पादों की बिक्री की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है। डिजिटल लेन-देन और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में किसानों की भागीदारी सीमित रही, जिससे वे योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा सके।

6. योजनाओं से संबंधित मुख्य चुनौतियाँ: सूचना का अभाव: कई किसानों को योजनाओं के लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं थी।

लाभ वितरण में देरी: सरकारी लाभ और बीमा दावों के निपटारे में औसतन 2 से 3 महीने का विलंब हुआ।

बिचौलियों की भूमिका: MSP खरीद केंद्रों और ऋण वितरण प्रणाली में कई किसानों ने बिचौलियों की दखलंदाजी की शिकायत की।

तकनीकी अवरोध: डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण कई किसान ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन का लाभ नहीं उठा सके।

समाप्ति

इस अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि कृषक कल्याण योजनाएँ किसानों की आय और कृषि उत्पादकता को सुधारने में सहायक रही हैं, लेकिन इनकी प्रभावशीलता को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। जागरूकता, पारदर्शिता, और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देकर इन योजनाओं के प्रभाव को अधिक

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

किसानों तक पहुँचाया जा सकता है। योजनाओं की जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए गाँव स्तर पर सूचना केंद्र और डिजिटल हेल्पडेस्क स्थापित करने की आवश्यकता है। लाभार्थियों को योजनाओं के बारे में सही और समय पर जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। MSP प्रणाली और कृषि विपणन को अधिक पारदर्शी और लाभदायक बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना आवश्यक है। सिंचाई और ग्रामीण सड़कों में निवेश बढ़ाकर किसानों की बाजार तक पहुँच आसान बनाई जा सकती है। डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाकर किसानों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में कार्य करना आवश्यक है। यदि सरकार और कृषि विभाग नीतिगत सुधारों को प्रभावी रूप से लागू करते हैं, तो कृषक कल्याण योजनाएँ किसानों की आय और जीवन स्तर में दीर्घकालिक सुधार ला सकती हैं।मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की कृषक कल्याण योजनाओं से संबंधित सर्वेक्षण से पता चलता है कि जिले के अधिकांश किसान इन योजनाओं के बारे में जागरूक हैं। सर्वेक्षण में शामिल कुल 500 उत्तरदाताओं में से 380 लोगों ने बताया कि वे इन योजनाओं से परिचित हैं, जो कि कुल संख्या का 76% है। यह प्रतिशत दर्शाता है कि जिले में अधिकतर किसानों तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंच चुकी है और वे संभवतः इनका लाभ उठा रहे हैं या उनकी प्रभावशीलता को समझ रहे हैं। दूसरी ओर, 120 उत्तरदाताओं, अर्थात 24% ने कहा कि वे इन योजनाओं से परिचित नहीं हैं। यह आंकड़ा यह इंगित करता है कि जिले में अब भी एक वर्ग ऐसा है जिसे इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। यह इस बात पर ध्यान आकर्षित करता है कि सरकार को अपने सूचना प्रसार के प्रयासों को और मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि अधिकतम किसानों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचे और वे उनका लाभ उठा सकें।

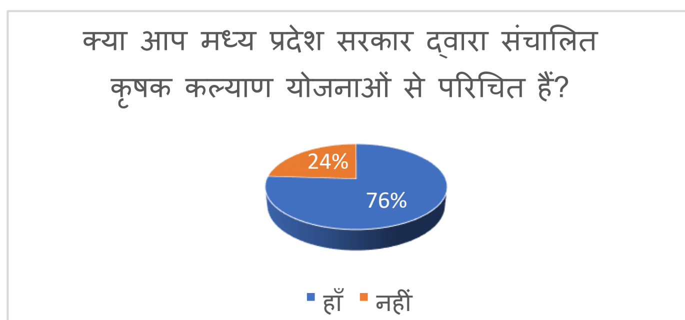

Fig 1: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कृषक कल्याण योजनायें।

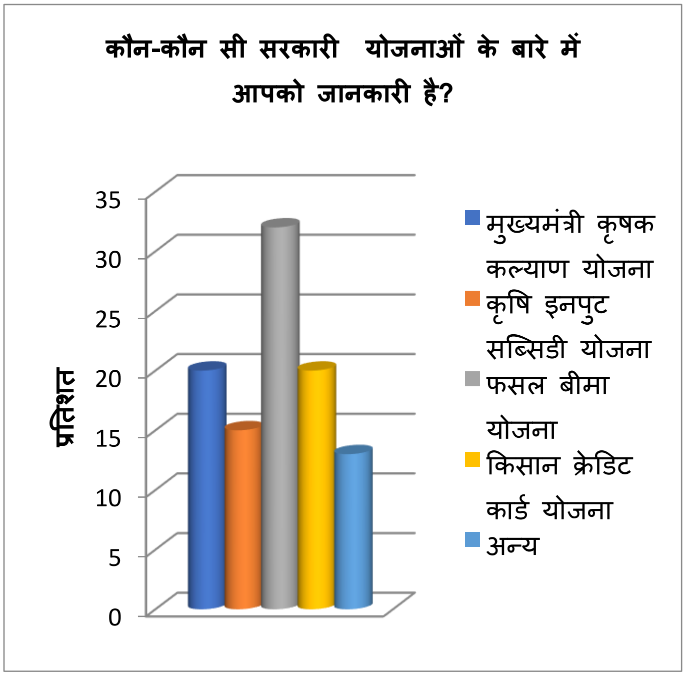

Fig 2: मध्यप्रदेश की सरकारी योजनाओं की जानकारी।

मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में किसानों से यह पूछने पर कि वे कौन-कौन सी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी रखते हैं, एक सर्वेक्षण से निम्नलिखित विवरण सामने आया। कुल 500 उत्तरदाताओं में से 160 लोगों (32%) ने बताया कि वे फसल बीमा योजना के बारे में जानते हैं, जो इस सूची में सबसे अधिक जागरूकता वाली योजना है। इसके बाद मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी 100-100 लोगों (20% प्रत्येक) ने दी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये योजनाएं भी किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के बारे में जानकारी रखने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 75 (15%) थी, जबकि अन्य योजनाओं के बारे में 65 लोगों (13%) ने जानकारी दी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ योजनाओं की जानकारी और जागरूकता व्यापक है, जबकि अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी की पहुंच अभी सीमित है। पन्ना जिले में एक सर्वेक्षण के माध्यम से यह जानने की कोशिश की गई कि कितने किसानों को सरकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिला है। कुल 500 उत्तरदाताओं में से 345 लोगों (69%) ने बताया कि उन्हें सरकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है। यह आंकड़ा सकारात्मक संकेत देता है कि जिले में अधिकांश किसान सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं और ये योजनाएं उनकी आजीविका में सुधार कर रही हैं।

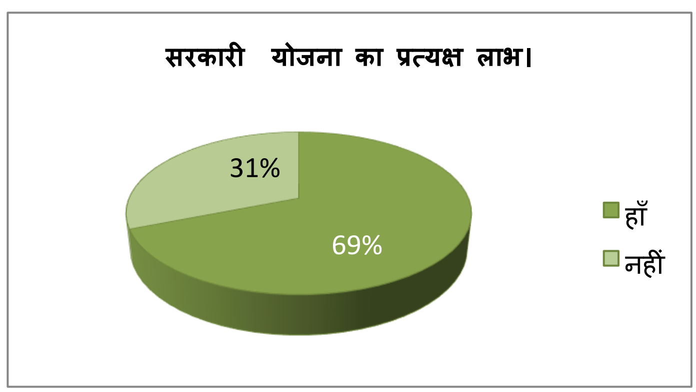

Fig 3: सरकारी योजना का प्रत्यक्ष लाभ।

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

वहीं, 155 उत्तरदाताओं (31%) ने कहा कि उन्हें इन योजनाओं का कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिला है। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि अभी भी कुछ ऐसे किसान हैं जो योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। इन लोगों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार को अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

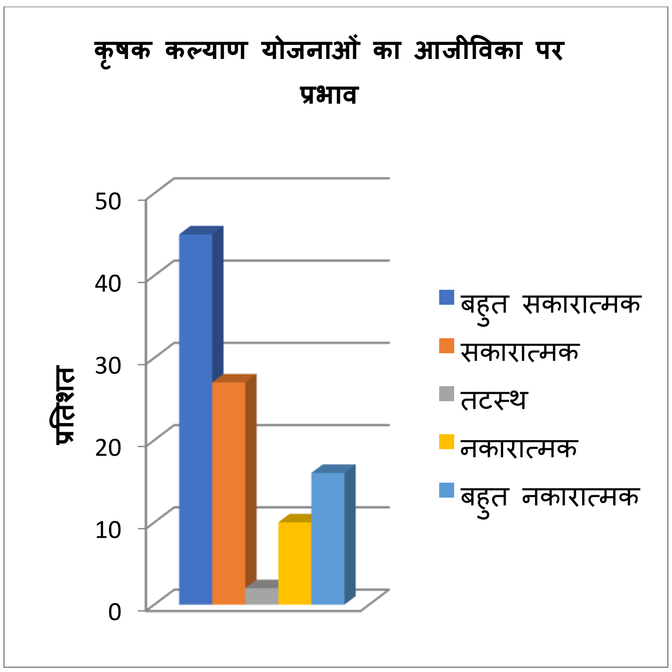

Fig 4: कृषक कल्याण योजनाओं का आजीविका पर प्रभाव

पन्ना जिले में किए गए सर्वेक्षण में किसानों से यह जानने की कोशिश की गई कि उनके अनुसार, कृषक कल्याण योजनाओं का उनकी आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ा है। सर्वेक्षण के परिणाम बताते हैं कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने इन योजनाओं के प्रभाव को सकारात्मक रूप में महसूस किया है। कुल 500 उत्तरदाताओं में से 225 लोगों (45%) ने बताया कि इन योजनाओं का उनकी आजीविका पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जबकि 135 लोगों (27%) ने इसे सकारात्मक बताया। यह दर्शाता है कि 72% किसानों के लिए इन योजनाओं का प्रभाव लाभदायक रहा है, जिससे उनकी आजीविका में सुधार हुआ है। हालांकि, 10 उत्तरदाताओं (2%) ने तटस्थ प्रतिक्रिया दी, जिसका मतलब है कि योजनाओं का उनके जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं, 50 उत्तरदाताओं (10%) ने नकारात्मक और 80 उत्तरदाताओं (16%) ने बहुत नकारात्मक प्रभाव की बात कही। ये आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं कि कुछ किसानों को इन योजनाओं से अपेक्षित लाभ नहीं मिला है या उनकी स्थितियों में सुधार नहीं हुआ है। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश किसानों ने योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव का अनुभव किया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण संख्या ऐसे किसानों की भी है जिन्होंने नकारात्मक अनुभवों की बात कही। नीति निर्माताओं के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे उन समस्याओं और चुनौतियों की

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

पहचान करें, जिनके कारण कुछ किसान योजनाओं से संतुष्ट नहीं हैं। इस प्रकार के अध्ययन सरकार को सुधारात्मक कदम उठाने में मदद करते हैं ताकि योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके और वे सभी किसानों के लिए अधिक उपयोगी बन सकें। पन्ना जिले में किए गए सर्वेक्षण में किसानों से पूछा गया कि कृषि इनपुट सब्सिडी योजना से प्राप्त लाभ का उनकी कृषि गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ा है। कुल 500 उत्तरदाताओं में से 160 किसानों (32%) ने बताया कि इस योजना के कारण उन्हें बेहतर कृषि इनपुट में निवेश करने की अनुमति मिली, जिससे उनकी कृषि गतिविधियों में सुधार हुआ।

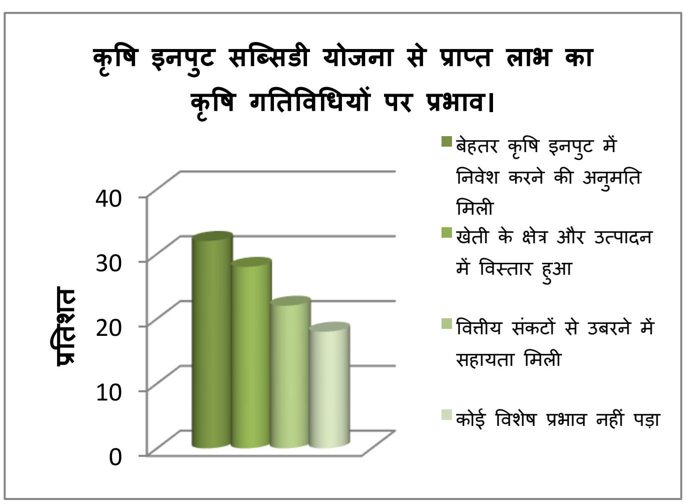

Fig 5: कृषि इनपुट सब्सिडी योजना से प्राप्त लाभ का कृषि गतिविधियों पर प्रभाव।

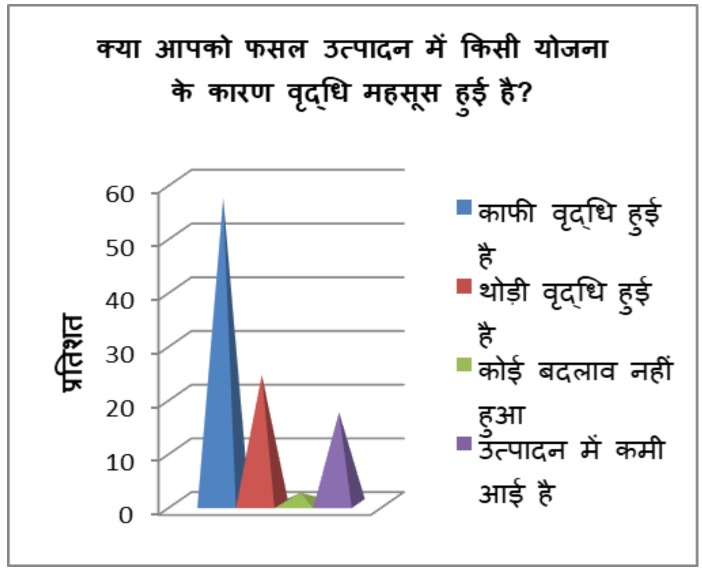

Fig 6: फसल उत्पादन में योजना के कारण हुई वृद्धि।

इसके अलावा, 140 उत्तरदाताओं (28%) ने कहा कि इस योजना से उनकी खेती के क्षेत्र और उत्पादन में विस्तार हुआ। यह दर्शाता है कि सब्सिडी ने कई किसानों को अपने कृषि प्रयासों को बढ़ाने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद की है। 110 उत्तरदाताओं (22%) ने बताया कि इस योजना ने उन्हें वित्तीय संकटों से उबरने में सहायता दी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योजना ने किसानों की आर्थिक स्थिरता में योगदान दिया है। हालांकि, 90 उत्तरदाताओं (18%) ने कहा कि उन्हें इस योजना से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। यह दिखाता है कि योजना का प्रभाव सभी किसानों पर समान नहीं रहा, और कुछ किसानों के लिए इसका लाभ सीमित रहा है।

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

पन्ना जिले में किए गए सर्वेक्षण में किसानों से यह पूछा गया कि कृषि यंत्रीकरण योजना का उनकी कृषि गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस सर्वेक्षण में कुल 500 किसानों ने भाग लिया, जिनकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण निम्नलिखित है:

बेहतर यंत्रों में निवेश की अनुमति मिली: 160 उत्तरदाताओं (32%) ने बताया कि इस योजना के तहत उन्हें बेहतर कृषि यंत्रों में निवेश करने का अवसर मिला, जिससे उनकी कृषि गतिविधियों में सुधार हुआ। इस प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि यंत्रीकरण योजना ने किसानों को उन्नत तकनीकी साधनों के उपयोग के लिए प्रेरित किया।

खेती के क्षेत्र और उत्पादन में विस्तार: 140 उत्तरदाताओं (28%) का मानना है कि इस योजना के कारण उनके खेती के क्षेत्र और फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है। यह दर्शाता है कि योजना ने किसानों को अपनी कृषि गतिविधियों को बढ़ाने और उत्पादन में वृद्धि करने में मदद की है।

वित्तीय संकटों से उबरने में सहायता: 110 उत्तरदाताओं (22%) ने कहा कि इस योजना से उन्हें आर्थिक संकटों से उबरने में मदद मिली। इससे स्पष्ट होता है कि योजना ने किसानों की आर्थिक स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा: 90 उत्तरदाताओं (18%) ने कहा कि उन्हें इस योजना से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। इस प्रतिक्रिया से यह पता चलता है कि यंत्रीकरण योजना का प्रभाव सभी किसानों पर समान रूप से नहीं पड़ा, और कुछ किसानों के लिए इसका लाभ सीमित रहा है।

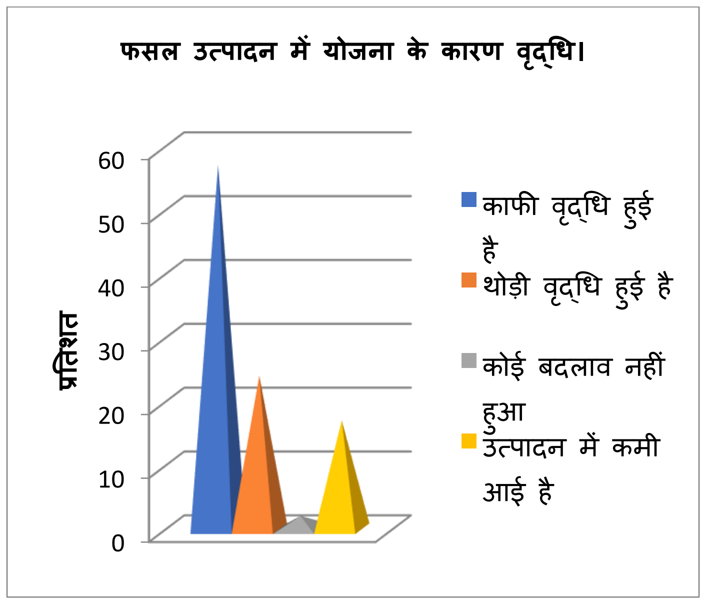

Fig 7: फसल उत्पादन में योजना के कारण वृद्धि।

पन्ना जिले में किए गए सर्वेक्षण में किसानों से यह पूछा गया कि क्या सरकारी योजनाओं के कारण उनकी वित्तीय स्थिति में कोई सुधार हुआ है। कुल 500 उत्तरदाताओं में से 335 किसानों (67%) ने बताया कि उनकी

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ है, जो दर्शाता है कि अधिकांश किसानों ने सरकारी योजनाओं का सकारात्मक लाभ महसूस किया है। इसके अलावा, 60 किसानों (12%) ने थोड़ा सुधार होने की बात कही, जिससे पता चलता है कि कुछ किसानों को भी योजनाओं से आंशिक आर्थिक लाभ मिला है। वहीं, 15 किसानों (3%) ने कहा कि उनकी वित्तीय स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, जबकि 90 किसानों (18%) ने बताया कि योजनाओं का उनके वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

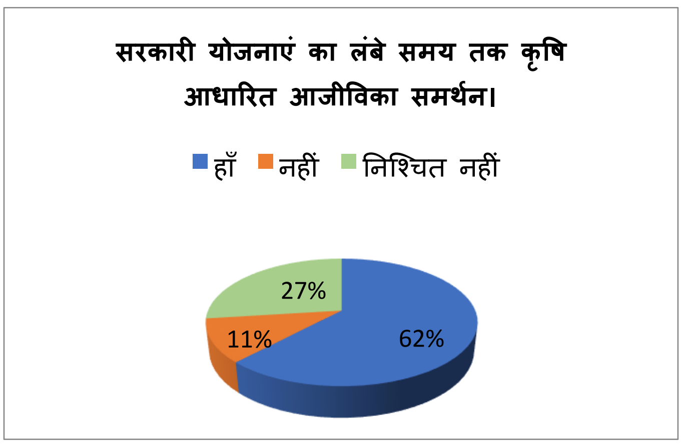

Fig 8: सरकारी योजनाएं का लंबे समय तक कृषि आधारित आजीविका समर्थन।

पन्ना जिले में किए गए एक सर्वेक्षण में किसानों से यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या वे मानते हैं कि सरकारी योजनाएं उनकी कृषि आधारित आजीविका को लंबे समय तक समर्थन दे सकती हैं। कुल 500 उत्तरदाताओं में से 310 किसानों (62%) ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और विश्वास जताया कि ये योजनाएं उनकी आजीविका को लंबे समय तक सहारा दे सकती हैं। इसके विपरीत, 55 किसानों (11%) ने इसे लेकर असहमति व्यक्त की और माना कि ये योजनाएं दीर्घकालिक रूप से सहायक नहीं होंगी। वहीं, 135 किसान (27%) निश्चित नहीं थे और उन्होंने अपनी अनिश्चितता व्यक्त की। इस सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि अधिकांश किसानों को इन योजनाओं पर भरोसा है, जबकि एक हिस्से में असमंजस और संदेह भी मौजूद है।

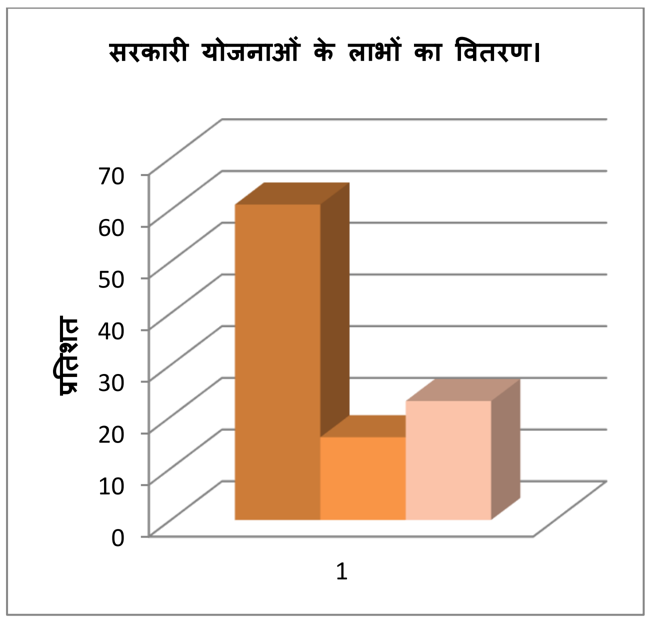

Fig 9: सरकारी योजनाओं के लाभों का वितरण।

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

पन्ना जिले में किए गए सर्वेक्षण में किसानों से पूछा गया कि क्या उनकी राय में सरकारी योजनाओं के लाभों का वितरण समय पर और समान रूप से होता है। कुल 500 उत्तरदाताओं में से 305 किसानों (61%) ने कहा कि लाभों का वितरण हमेशा समय पर और समान रूप से होता है, जो यह दर्शाता है कि अधिकांश किसानों को योजनाओं के वितरण प्रणाली पर भरोसा है। इसके अलावा, 80 किसानों (16%) का मानना है कि वितरण प्रक्रिया केवल कभी-कभी समय पर होती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कुछ किसानों को योजनाओं के लाभ अनियमित समय पर प्राप्त होते हैं। वहीं, 115 किसानों (23%) ने कहा कि लाभों का वितरण अनियमित होता है, जिससे उनके अनुभव में योजनाओं का लाभ समान रूप से सभी तक नहीं पहुँच पाता। इन प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि जबकि अधिकांश किसानों को सरकारी योजनाओं का वितरण समय पर मिलता है, कुछ किसानों को इसमें अनियमितता का सामना करना पड़ता है। पन्ना जिले में किए गए सर्वेक्षण में किसानों से पूछा गया कि क्या सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सहायता उनके कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त है। कुल 500 उत्तरदाताओं में से 60 किसानों (12%) ने बताया कि सहायता बहुत पर्याप्त है, जबकि 25 किसानों (5%) ने इसे पर्याप्त माना, जो दर्शाता है कि केवल एक छोटा हिस्सा इस सहायता को कृषि कार्यों के लिए संतोषजनक मानता है।

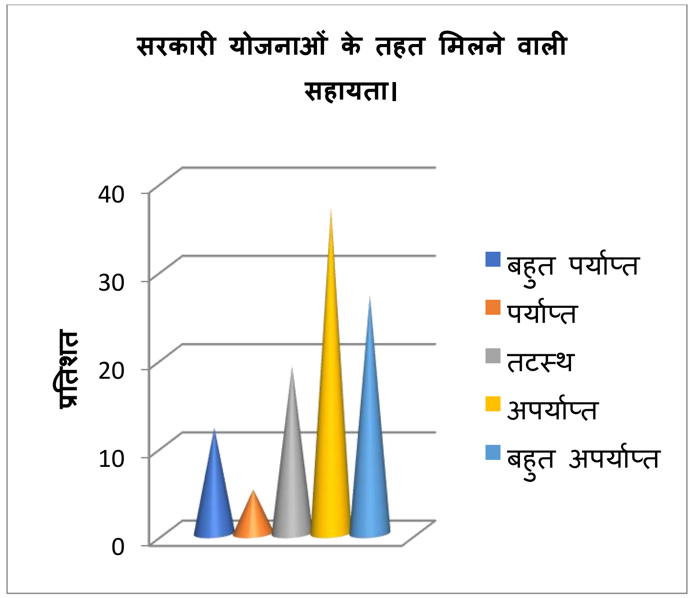

Fig 10: सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सहायता।

इसके विपरीत, 185 किसानों (37%) ने कहा कि सहायता अपर्याप्त है, और 135 किसानों (27%) ने इसे बहुत अपर्याप्त बताया। इन प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि अधिकांश किसानों को योजनाओं के तहत मिलने वाली सहायता को पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। वहीं, 95 किसान (19%) तटस्थ रहे, जिनकी राय सकारात्मक या नकारात्मक नहीं थी।

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

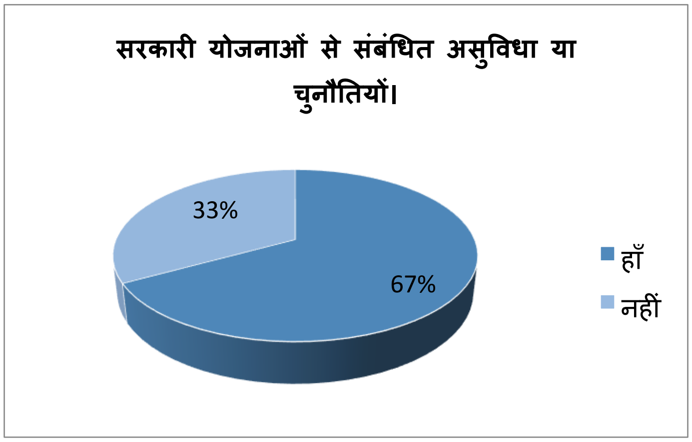

Fig 11: सरकारी योजनाओं से संबंधित असुविधा या चुनौतियां।

पन्ना जिले में किए गए एक सर्वेक्षण में किसानों से पूछा गया कि क्या उन्हें सरकारी योजनाओं से संबंधित किसी प्रकार की असुविधा या चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कुल 500 उत्तरदाताओं में से 335 किसानों (67%) ने बताया कि उन्हें इन योजनाओं के उपयोग में कुछ कठिनाइयों का अनुभव हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में कई किसान बाधाओं का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर, 165 किसानों (33%) ने कहा कि उन्हें कोई असुविधा या चुनौती नहीं झेलनी पड़ी। यह समूह योजनाओं के उपयोग में सहजता महसूस करता है और उनके अनुभव अपेक्षाकृत सकारात्मक रहे हैं। पन्ना जिले में किए गए एक सर्वेक्षण में किसानों से यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या वे मानते हैं कि सरकारी योजनाएं उनकी आय और कृषि उत्पादकता में सुधार करने में सहायक हैं। कुल 500 उत्तरदाताओं में से 355 किसानों (71%) ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, यह दर्शाते हुए कि उनकी राय में इन योजनाओं ने उनकी आय और उत्पादकता में सुधार किया है। वहीं, 40 किसानों (8%) ने कहा कि योजनाएं उनकी आय और उत्पादकता में वृद्धि करने में सहायक नहीं हैं, जो बताता है कि कुछ किसानों को योजनाओं से अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके अतिरिक्त, 105 किसान (21%) इस बारे में अनिश्चित थे, जिससे पता चलता है कि कुछ किसान अभी भी योजनाओं के प्रभाव को लेकर स्पष्ट नहीं हैं।

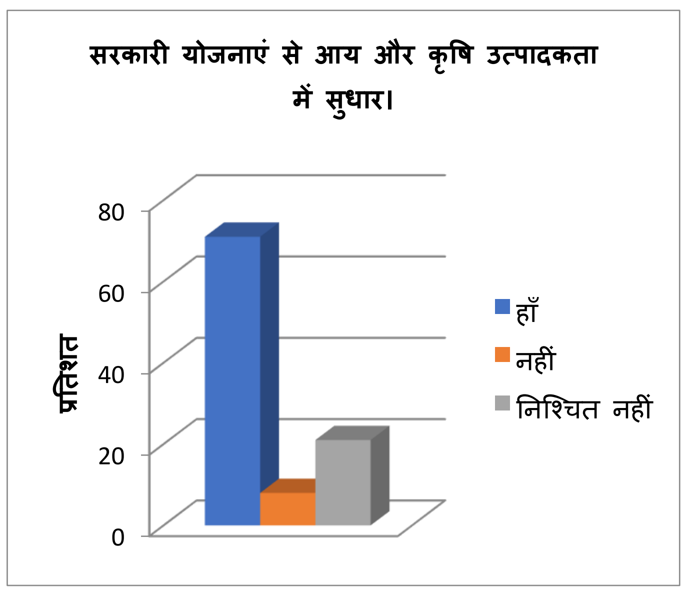

Fig 12: सरकारी योजनाएं से आय और कृषि उत्पादकता में सुधार।

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

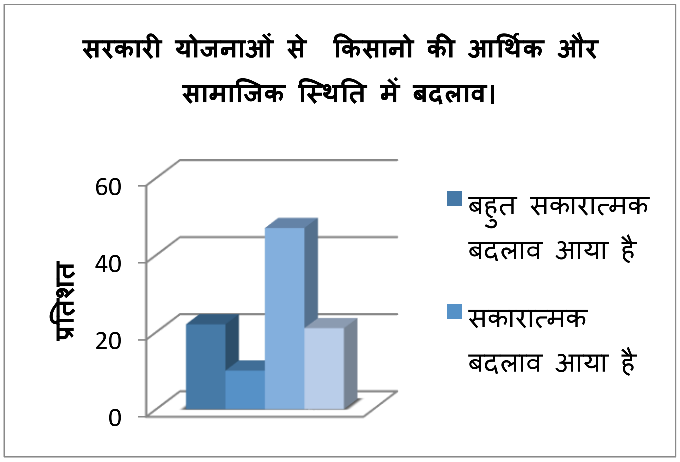

चित्र 13: सरकारी योजनाओं से किसानो की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बदलाव।

पन्ना जिले में किए गए सर्वेक्षण में किसानों से यह पूछा गया कि उनके अनुसार, सरकार द्वारा दी जा रही सहायता से उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में क्या बदलाव आया है। सर्वेक्षण के परिणाम निम्नलिखित थे:

बहुत सकारात्मक बदलाव आया है: 110 किसानों (22%) ने बताया कि सरकारी सहायता से उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बहुत सकारात्मक बदलाव आया है। इन किसानों का मानना है कि सरकारी योजनाओं ने उनकी जीवनशैली और समृद्धि में महत्वपूर्ण सुधार किया है, जिससे वे अपने कृषि कार्यों और परिवार की भलाई में अधिक सक्षम महसूस करते हैं।

सकारात्मक बदलाव आया है: 50 किसानों (10%) ने कहा कि सरकारी योजनाओं ने उनकी स्थिति में सकारात्मक बदलाव किया है, लेकिन यह बदलाव उतना बड़ा नहीं था जितना कुछ अन्य किसानों ने अनुभव किया। वे योजनाओं से प्राप्त सहायता को आंशिक रूप से फायदेमंद मानते हैं, लेकिन उनका पूरा प्रभाव सीमित है।

कोई विशेष बदलाव नहीं आया: 235 किसानों (47%) ने बताया कि सरकारी योजनाओं से उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ। इन किसानों का अनुभव यह था कि सरकारी योजनाओं का असर उनके जीवन पर ज्यादा नहीं पड़ा और वे पहले की तरह ही अपनी कृषि गतिविधियों में व्यस्त हैं। इस परिणाम से यह स्पष्ट होता है कि योजनाओं का प्रभाव कुछ किसानों तक ही सीमित रहा।

नकारात्मक बदलाव आया है: 105 किसानों (21%) ने महसूस किया कि सरकारी योजनाओं से उनकी स्थिति में नकारात्मक बदलाव आया है। इस समूह के किसानों का मानना है कि योजनाओं के बावजूद उन्हें आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि कुछ समस्याएं और भी बढ़ गईं, जैसे कि योजनाओं के

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

कार्यान्वयन में अनियमितताएं या समय पर सहायता का न मिलना।

निष्कर्ष

यह अध्ययन पन्ना जिले में संचालित कृषक कल्याण योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करता है और यह दर्शाता है कि इन योजनाओं ने किसानों की आर्थिक, सामाजिक और कृषि उत्पादकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि 76% किसान इन योजनाओं के बारे में जागरूक हैं, लेकिन उनमें से केवल 69% किसानों को ही योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिला है। यह दर्शाता है कि जागरूकता और पहुँच के बीच एक अंतर बना हुआ है, जिससे यह आवश्यक हो जाता है कि योजनाओं के प्रचार-प्रसार और कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) और कृषि ऋण माफी योजना ने किसानों को वित्तीय राहत प्रदान की है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता में सुधार हुआ है। वहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 54% किसानों को उनकी फसल हानि की आंशिक भरपाई मिली, जबकि 62% किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के माध्यम से कर्ज की आसान उपलब्धता की सुविधा प्राप्त की। हालांकि, सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि एमएसपी प्रणाली का प्रभाव सभी किसानों पर समान नहीं पड़ा, कुछ किसानों को इसका लाभ मिला, जबकि अन्य को बाज़ार मूल्य की अस्थिरता से नुकसान उठाना पड़ा। योजनाओं के कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ भी सामने आईं। 24% किसानों को इन योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं थी, जिससे वे इनके लाभ से वंचित रह गए। इसके अलावा, कई किसानों ने सरकारी लाभ मिलने में देरी की शिकायत की, खासकर फसल बीमा दावों के निपटारे में औसतन 2 से 3 महीने का समय लगना एक प्रमुख समस्या के रूप में उभरकर आया। भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका भी एक प्रमुख बाधा रही, जिससे MSP खरीद केंद्रों पर पारदर्शिता की कमी देखी गई। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-गवर्नेंस प्रणाली की उपयोगिता सीमित रही, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी समझ की कमी के कारण किसान ऑनलाइन आवेदन और योजनाओं से जुड़ने में असमर्थ रहे। इन चुनौतियों के समाधान के लिए नीतिगत सिफारिशों की

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

आवश्यकता है। जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्राम स्तर पर कृषि सहायता केंद्रों और पंचायत आधारित सूचना अभियान चलाए जाने चाहिए। लाभार्थियों को योजनाओं की संपूर्ण जानकारी देने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन और हेल्पडेस्क सेवाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, लाभ वितरण की प्रक्रिया को तेज़ और पारदर्शी बनाने के लिए सीधे बैंक हस्तांतरण (DBT) प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। एमएसपी प्रणाली को मजबूत करने के लिए डिजिटल लेन-देन को अनिवार्य करना चाहिए और ई-नाम (e-NAM) पोर्टल के माध्यम से किसानों को सीधे बाज़ार से जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए। इसके अलावा, सिंचाई और बुनियादी ढाँचे में सुधार की आवश्यकता है, जिसमें सौर ऊर्जा आधारित पंप और ड्रिप सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा दिया जा सकता है। किसानों की उपज को बेहतर बाज़ारों तक पहुँचाने के लिए ग्राम सड़क परियोजनाओं और भंडारण सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, फसल बीमा दावों के निपटारे की प्रक्रिया को 30 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत 0% ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराने की योजना विकसित की जानी चाहिए। भविष्य में इस विषय पर और गहन शोध की आवश्यकता है, जिससे यह समझा जा सके कि क्या ये योजनाएँ किसानों की स्थायी आय वृद्धि में सहायक हो रही हैं और क्या ये योजनाएँ उन्हें कर्ज़ के जाल से मुक्त करने में सफल रही हैं। साथ ही, क्षेत्रीय तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह विश्लेषण किया जाना चाहिए कि किन जिलों में ये योजनाएँ अधिक प्रभावी रही हैं और किन कारणों से कुछ क्षेत्रों में इनका अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः, यह अध्ययन दर्शाता है कि मध्य प्रदेश की कृषक कल्याण योजनाएँ किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक रही हैं, लेकिन इनकी प्रभावशीलता को और अधिक सशक्त करने के लिए जागरूकता, पारदर्शिता और तकनीकी सुधार आवश्यक हैं। यदि सरकार नीतिगत सिफारिशों को प्रभावी रूप से लागू करती है, तो यह योजनाएँ अधिक किसानों तक पहुँचेंगी और उनके जीवन में ठोस सुधार लाएँगी। "एक सशक्त किसान ही समृद्ध भारत की नींव है"

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

- इस लक्ष्य को साकार करने के लिए कृषक कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।

संदर्भ

1. पीयूषी नेमा (2024), "सागर संभाग में किसानों के ऋण बोझ पर नाबार्ड की ब्याज सब्सिडी योजनाओं का प्रभाव", बुन्देलखण्ड रिसर्च जर्नल |जून, 2024|खंड 2, अंक 1
2. कन्हैया आहूजा, गणेश कावड़िया, अनंत ग्वाल और आनंद श्रीवास्तव, "मध्यप्रदेश में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा ऋण संवितरण: एक अंतर- जिला विश्लेषण", मध्यप्रदेश जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, 2008 वॉल्यूम। 13, अंक 1
3. चतुर्वेदी पूनम, वाणी गौरव कुमार, राजपूत अंकिता, "मध्यप्रदेश के किमोर पठार कृषि-जलवायु क्षेत्र में कुल फसल राजस्व में गतिशील परिवर्तनों का अपघटन विश्लेषण", आर्थिक मामले, 2023, खंड: 68, अंक: 1, डीओआई: 10.46852/0424-2513.1.2023.8
4. बाला बी और शर्मा एसडी,2005 "हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में कृषि के विविधीकरण और व्यावसायीकरण की आय और रोजगार पर प्रभाव", कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान समीक्षा 18: 261-269।
5. अली, जे. और एस. कपूर,2018 "फलों और सब्जियों के उत्पादन में जोखिमों पर किसान की धारणा: उत्तर प्रदेश का एक अनुभवजन्य अध्ययन", कृषि। इकोन. रेस. रेव., 21(कॉन्फ़. नं.): 317-326।
6. एनी बडकुल, मोहम्मद फ़िरोज़ सी और दीप्ति बेंदी, "सामाजिक- आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानताओं की खोज: मध्यप्रदेश, भारत का एक मामला", स्प्रिंगर, 2022, डीओआई: https://doi.org/10.1007/978 -3-030-96760-4_9
7. रजनी जैन, प्रेमचंद, प्रियंका अग्रवाल, सुलक्षणा राव और सुरेश पा, "आकांक्षी जिलों में कृषि बुनियादी ढांचे की उपयुक्तता का निर्धारण: बुंदेलखण्ड का एक केस अध्ययन", इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, 2021।
8. गगन त्रिपाठी, अर्पित ढोडिया, अनमोल गिरी, वीणा राठौड़, अमन वर्मा, अनूप शुक्ला, ललित कुमार वर्मा, 2023 - "एशियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी", वॉल्यूम

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001

41 [अंक 11] डीओआई: https://doi.org/ 10.9734/ajaees/2023/v41i112261

9. संदीप कौर, हेमराज, हरप्रीत सिंह और विजय कुमार चट्टू, "भारत में फसल बीमा नीतियां: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक अनुभवजन्य विश्लेषण", खंड 9 अंक 11, एमपीडीआई, 2021, डीओआई: https://doi .org/10.3390/risks9110191

10. प्रो. रतन लाल गोदारा, डॉ. प्रताप सिंह और डॉ. संजय सिंगला, "भारत में कृषि क्रेडिट: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लेटेस्ट ट्रेंड्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आईजेएलटीईटी) वॉल्यूम। 3 अंक 3 जनवरी 2014।

11. मेघा साहू, जे.एस. रघुवंशी और ए.एम. जौलकर, "मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले के जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के ऋण के उपयोग पैटर्न और डायवर्सन पर एक अध्ययन" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड रिसर्च (आईजेएएसआर) । 7, अंक 2, अप्रैल 2017, 405-412।

Publisher: Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Police Lines Road, Panna Road Chhatarpur (M.P) - 471001